न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और एन के सूद के समक्ष

रविंद्र पाल सिंह—याचिकाकर्ता

बनाम

यू टी चंडीगढ़ और अन्य— प्रतिवादी

C.W.P. 9749 of 1998

16 जनवरी 2001

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226—आवंटी प्रीमियम की किश्तों का भुगतान करने में विफल रहे — संपदा अधिकारी ने पट्टा रद्द करने का आदेश दिया और उन्हें कई अवसर देने के बाद साइट को फिर से शुरू करना - अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को खारिज कर दिया क्योंकि वे बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे - पुनरीक्षण याचिका दायर करने में 7 साल से अधिक की लंबी और अस्पष्ट देरी - पुनरीक्षण प्राधिकारी ने इस आधार पर पुनरीक्षण याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया देरी के कारण - हालाँकि याचिकाकर्ता को कार्यवाही के बारे में पूरी जानकारी थी फिर भी उसने भुगतान करने के विभिन्न अवसरों का लाभ नहीं उठाया - रिट खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया कि पीड़ित पक्ष केवल कानून के अनुसार 'अपील' और 'संशोधन' का उपाय ढूंढ सकता है। यदि प्रावधान परिसीमा अवधि निर्धारित करता है, तो पीड़ित व्यक्ति को उस समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। क़ानून में निर्धारित मापदंडों, यदि कोई हो, के भीतर छूट की अनुमति दी जा सकती है या केवल तभी दी जा सकती है जब देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिया गया हो। पार्टी वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकती और फिर कमजोर स्पष्टीकरण देकर देरी को माफ करने पर जोर नहीं दे सकती। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की अपील मुख्य प्रशासक द्वारा 9 अप्रैल, 1990 को खारिज कर दी गई थी। उस तारीख के बाद, याचिकाकर्ता ने 10 फरवरी, 1998 तक सात साल से अधिक समय

तक इंतजार किया था जब उसने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसके लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और न अतिरिक्त हलफनामे में कोई सफाई दी गई। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी को यह विचार करने का अधिकार था कि नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है। सलाहकार ने देरी के आधार पर पुनरीक्षण याचिका खारिज करके कोई गलती नहीं की है।

(अनुच्छेद 11 और 14)

एस सी कपूर, वरिष्ट अधिवक्ता, के साथ आशीष कपूर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

दीपक अग्निहोत्री, प्रतिवादी के अधिवक्ता

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, (मौखिक)

(1) क्या प्रशासक के सलाहकार ने देरी के आधार पर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करके गलती की है? यह प्राथमिक प्रश्न है जो इस मामले में विचार के लिए उठता है। इस मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक कुछ तथ्यों पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है।

(2) साइट नंबर 302, सेक्टर 35-डी, चंडीगढ़ के लीज-होल्ड अधिकार 9 जुलाई, 1985 को नीलाम किए गए। याचिकाकर्ता और उसकी मां ने रुपये 2,30,000 की बोली दी। यह बोली स्वीकार कर ली गई। 4 अगस्त, 1985 को याचिकाकर्ता और उसकी मां (जिनकी मृत्यु हो चुकी है) के पक्ष में आवंटन पत्र जारी किया गया था। इस पत्र की एक प्रति संलग्नक पी-1 के रूप में प्रस्तुत या रिकार्ड की गई है। आवंटियों ने प्रीमियम का 25% यानी रूपये 57,000/- का भुगतान किया था। शेष राशि की रूपये 65,731.15 पी. प्रत्येक, की तीन वार्षिक किस्तों में भुगतान करना था। याचिकाकर्ता और उसकी मां को जमीन का किराया भी रुपये 5,750 प्रति वर्ष का भुगतान करना पड़ा। उन्होंने पहली किस्त का भुगतान कर दिया। हालाँकि, उन्होंने दूसरी किस्त का भुगतान नहीं किया जो 9 जुलाई, 1987 को देय थी। संपदा अधिकारी ने पट्टा रद्द करने की कार्यवाही शुरू की। आवंटियों को 11 नवंबर, 1988 को एक नोटिस दिया गया था। इसके बाद चार मौके दिये गये. मामले को 6 दिसंबर, 1988, 7 मार्च, 1989, 13 जून, 1989 और 4 जुलाई, 1989 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अंततः, 4 जुलाई, 1989 के आदेश के तहत संपदा अधिकारी ने पट्टे को रद्द करने और पहले ही भुगतान की गई राशि के एक हिस्से को जब्त करने का आदेश दिया। आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान

याचिकाकर्ता सहित दो आवंटियों ने चंडीगढ़ लीज होल्ड ऑफ साइट्स एंड बिल्डिंग रूल्स, 1973 के नियम 22 के तहत अपील दायर की। आवंटियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कई अवसर दिए गए। इसका भुगतान नहीं किया गया. अंत में, 9 अप्रैल, 1990 के आदेश के तहत मुख्य प्रशासक ने कहा कि "अपीलकर्ता सरकारी बकाया का भुगतान करने के इच्छुक नहीं हैं। पट्टे को रद्द करने का आधार अपीलकर्ताओं द्वारा दूसरी किस्त की राशि का भुगतान न करना था, जो 9 जुलाई, 1987 को देय थी। प्रीमियम की तीसरी किस्त, जो 9 जुलाई, 1988 को देय थी, का भी भुगतान नहीं किया गया है। "। इस प्रकार, अपील खारिज कर दी गई।

(3) इस आदेश के पारित होने के बाद, वर्तमान याचिकाकर्ता जो अपनी मां के साथ दो आवंटियों में से एक था, फरवरी 1998 तक चुप रहा। उसने सात साल से अधिक समय तक मुख्य प्रशासक द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। साल। 10 फरवरी, 1998 को पुनरीक्षण याचिका सलाहकार के समक्ष दायर की गई थी। इस याचिका को प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया क्योंकि - उसने पुनरीक्षण याचिका "दाखिल करने में देरी" को नजरअंदाज करने में खुद को असमर्थ पाया। उनका विचार था कि यदि इतनी लंबी देरी को माफ कर दिया गया, तो अधिनियम और नियमों के प्रावधान पूरी तरह से अप्रभावी हो जायेंगे। आदेशों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है। वह प्रार्थना करते हैं कि 4 जुलाई, 1989, 9 अप्रैल, 1990 और 25 अप्रैल, 1998 के आदेशों को, जिनकी प्रतियां क्रमशः अनुलग्नक पी-5, पी-6 और पी-8 के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, रद्द किया जाए।

(4) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे का खंडन करते हुए प्रतिवादी की ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया है। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया गया था। यह बताया गया कि 11 दिसंबर, 1998 को आयोजित नीलामी में इसी तरह की साइट पर लीज-होल्ड अधिकार रुपये 16,30,000 में बेचे गए थे। तीन महीने से भी कम समय के बाद, उसी सेक्टर में एक और साइट रुपये 24,70,000 में बेची गई थी। इस आधार पर, यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राहत, जो पट्टे के पैसे का भुगतान करने में विफल रही थी, अस्वीकार करने योग्य है।

(5) पक्षों के वकील को सुना गया है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सुभाष कपूर का तर्क है कि मामले की परिस्थितियों में देरी माफ करने योग्य है। उन्होंने आगे कहा कि बहाली का आदेश पारित होने से पहले याचिकाकर्ता को संपदा अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अत: विवादित आदेश निरस्त किये जायें। यह भी तर्क दिया गया कि किरायेदार को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। इन आधारों पर वकील ने प्रार्थना की है कि विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से किए गए दावे का प्रतिवादीयों की ओर से उपस्थित श्री दीपक अग्निहोत्री ने खंडन किया है।

(7) विचार हेतु उठने वाले तीन प्रश्न हैं:-

1. क्या प्राधिकरण ने देरी के आधार पर पुनरीक्षण याचिका खारिज करके गलती की है?
2. क्या याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया और क्या उस आधार पर आदेश रद्द कर दिया जाना चाहिए?

3. क्या कथित किरायेदार पर नोटिस की तामील न होने के कारण आक्षेपित आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं?

(8) अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता और उसकी मां को संपत्ति अधिकारी द्वारा पारित 4 जुलाई 1989 के आदेश के बारे में पता था जिसके द्वारा साइट को फिर से शुरू किया गया था। उन्होंने मुख्य प्रशासक के समक्ष नियम 22 के तहत अपील दायर की थी। यह अपील 9 अप्रैल, 1990 को खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता नियमों के तहत 30 दिनों की अवधि के भीतर पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता था। उन्होंने 10 फरवरी, 1998 तक चुप रहने का विकल्प चुना था। याचिका में एकमात्र स्पष्टीकरण यह दिया गया था कि उन्हें भारी नुकसान हुआ था। उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थीं. वह कैंसर से पीड़ित थीं और चार साल तक बिस्तर पर रहीं। आख़िरकार, उसकी मृत्यु हो गई। उसके इलाज पर काफी रकम खर्च हुई. इस प्रकार, परिवार को नुकसान हुआ और वह बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सका।

(9) याचिकाकर्ता की मां कब बीमार पड़ीं? उसका इलाज कहाँ किया गया? वो कब मरी ? कुछ भी खुलासा नहीं किया गया. इस याचिका की

सुनवाई में भी याचिकाकर्ता को ब्योरा देने का मौका दिया गया था. उन्होंने 15 जनवरी, 2001 के एक हलफनामे के साथ 2001 का सिविल मिसलेनियस संख्या 1180 दायर किया था। याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया एकमात्र स्पष्टीकरण पैरा 4 में निहित है। मैं इसे इस प्रकार पढ़ता हूं: -

"कि अभिसाक्षी की मां, जो उसके साथ सह-आवंटी थी, कैंसर से पीड़ित थी और अपने निधन से पहले चार साल से अधिक समय तक बिस्तर पर रही थी। सबसे पहले अभिसाक्षी की मां ने वर्ष 1986 में डॉक्टर से परामर्श लिया और वह कैंसर से पीड़ित पाई गईं। उन्होंने वर्ष 1989, 1990 में डॉक्टरों से परामर्श लिया। इन सभी वर्षों के दौरान वह विभिन्न डॉक्टरों और (अलग-अलग शहरों में) इलाज कराती रहीं।

(10) आगे कहा गया है कि फरवरी 1990 में उन्हें फिरोजपुर स्थानांतरित कर दिया गया जहां 5 मार्च 1990 को उनकी मृत्यु हो गई।

(11) इस हलफनामे के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की मां की मृत्यु मार्च, 1990 में हो गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता की अपील 9 अप्रैल, 1990 को मुख्य प्रशासक द्वारा खारिज कर दी गई थी। उस तारीख के बाद, याचिकाकर्ता ने सात साल से अधिक समय तक यानी 10 फरवरी, 1998 तक इंतजार किया था जब उन्होंने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इस देरी के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया ना ही अतिरिक्त हलफनामे में कोई सफाई दी गई। इस स्थिति में, हम यह मानने के लिए सहमत नहीं हैं कि सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करके कानूनी त्रुटि की है। इसमें सात साल से अधिक की लंबी और अस्पष्ट देरी हुई। इस देरी के लिए कभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी को यह विचार करने का अधिकार था कि नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है।

(12) श्री कपूर का तर्क है कि विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा देरी को माफ कर दिया गया है। सबसे पहले वकील ने जसबीर कौर बनाम यू.टी. चंडीगढ़ और अन्य (1),में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य के फैसले का हवाला दिया है। यू हमने इस फैसले का अध्ययन किया है। आवंटी समय पर भुगतान करने में विफल रहा था, हालांकि, न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार उसने भुगतान कर दिया था। इस प्रकार,

उस मामले में लागू आदेश को रद्द कर दिया गया। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि देरी के प्रश्न पर उनके आधिपत्य द्वारा कोई राय व्यक्त नहीं की गई। वास्तव में, पैरा 4 में यह स्पष्ट रूप से देखा गया था कि वे "इस अपील में उठाए गए कानून के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे थे"। इस प्रकार, यह निर्णय इस प्रस्ताव का अधिकार नहीं है कि देरी चाहे जो भी हो, सक्षम प्राधिकारी इसे अनदेखा करने के लिए बाध्य है और उच्च न्यायालय को आवंटी को राहत देनी होगी। इस स्थिति का सामना करते हुए, विद्वान वकील ने कश्मीर चंद बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और अन्य (2) में सर्वोच्च न्यायालय के अपने आधिपत्य के निर्णय का उल्लेख किया है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। अवसर के बावजूद, प्रतिवादीयों की ओर से कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था। इस स्थिति में, उनके आधिपत्य ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपील का निपटान करने में प्रसन्नता व्यक्त की: -

"यद्यपि जवाब दाखिल करने में समय लिया गया, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा इसे दाखिल नहीं किया गया। ऐसा श्री के.बी.रोहतगी, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने 12% ब्याज के साथ राशि की दो किश्तें पहले ही जमा कर दी हैं और एक किस्त बकाया है। हम प्रथम दृष्टया वकील के बयान को सही मानते हैं। यदि उनका भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो अपीलकर्ता को आज से 4 महीने की अवधि के भीतर शेष राशि का भुगतान करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि उसने पहले से ही जमा नहीं किया है या यदि वह निर्देशानुसार राशि के भुगतान में चूक करता है, तो यह आदेश रद्द हो जाएगा और उच्च न्यायालय का आदेश बहाल हो जाएगा।

(13) इस मामले में भी यह नहीं अभिनिर्धारित किया गया कि प्राधिकरण देरी को नजरअंदाज करने के लिए बाध्य है।

(14) हमारे विचार में, पीड़ित पक्ष केवल कानून के अनुसार 'अपील' और 'संशोधन' का उपाय ढूंढ सकता है। यदि प्रावधान परिसीमा अवधि निर्धारित करते हैं, तो पीड़ित व्यक्ति को उस समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। क़ानून में निर्धारित मापदंडों, यदि कोई हो, के भीतर छूट की अनुमति दी जा सकती है या केवल तभी दी जा सकती है जब देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिया गया हो। पार्टी वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकती और फिर कमजोर स्पष्टीकरण देकर देरी को माफ

करने पर जोर नहीं दे सकती। वर्तमान मामले में, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता ने पर्याप्त कारण नहीं बताया है।

(15) उपरोक्त के दृष्टिगत प्रथम प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता के विरूद्ध दिया जाता है। यह माना जाता है कि सलाहकार ने देरी के आधार पर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने में गलती नहीं की है।

(16) श्री कपूर का तर्क है कि याचिकाकर्ता दो आवंटियों में से एक था। पट्टे को रद्द करने और साइट को फिर से शुरू करने की कार्यवाही शुरू करने के संबंध में नोटिस केवल श्रीमती करतार कौर को दिया गया था और उसे नहीं। इस प्रकार, आक्षेपित कार्यवाही निष्प्रभावी हो जाती है।

(17) याचिका के पैराग्राफ 8 में, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने नियम 12(3) के तहत एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-2 के रूप में प्रस्तुत की गई है। आगे कहा गया है कि "इस नोटिस को पढ़ने से पता चलेगा कि यह श्रीमती करतार कौर व अन्य को संबोधित किया गया था। इस प्रकार, नोटिस न तो याचिकाकर्ता को संबोधित था जो सह-खरीदार था और न ही उसे भेजा गया था।'' याचिकाकर्ता ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उसे कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। ऐसा कोई सुझाव भी नहीं है कि उनकी मां ने उन्हें कार्यवाही लंबित होने की जानकारी नहीं दी हो। यह स्वीकृत स्थिति है कि कार्यवाही 5 नवंबर, 1986 को शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता की मां उस तारीख को जीवित थीं। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि वह उससे अलग रह रहा था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता को कार्यवाही की लंबितता के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने मुख्य प्रशासक के समक्ष अपने द्वारा दायर अपील के आधार भी प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे यह पता चले कि उसने ऐसा दावा उसने किया था कि उसे नोटिस नहीं दिया गया था। वास्तव में, यह स्पष्ट है कि संपत्ति अधिकारी द्वारा पट्टा रद्द करने और साइट को फिर से शुरू करने का आदेश देने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा अपनी मां के साथ परिसीमा अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई के दौरान भी, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष यह सुझाव नहीं दिया गया कि नोटिस तामील नहीं किया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका अनुबंध पी-7 के रूप में रिकॉर्ड पर है। विद्वान वकील पुनरीक्षण

याचिका में किसी भी ऐसे कथन का उल्लेख नहीं कर पाए जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता को कार्यवाही की सूचना नहीं थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता केवल आदेश को चुनौती देने का बहाना ढूंढ रहा है। दरअसल, उन्हें कार्यवाही की सूचना थी. यह अलग बात है कि याचिकाकर्ता ने भुगतान करने के लिए विभिन्न अवसरों का लाभ नहीं उठाया।

(18) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिया जाता है।

(19) श्री कपूर ने तर्क दिया है कि पट्टा रद्द करने की कार्यवाही विकृत है क्योंकि किरायेदार को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। क्या ऐसा है ?

(20) याचिकाकर्ता द्वारा किया गया एकमात्र कथन रिट याचिका के पैराग्राफ 12 में निहित है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-
"यहाँ यह कहा जा सकता है कि यद्यपि किरायेदार का परिसर पर कब्ज़ा था फिर भी रद्दीकरण आदेश पारित होने से पहले उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था।"

(21) किरायेदार कौन था? परिसर को कब किराये पर दिया गया था? किराया कितना था? क्या कोई किरायानामा था? क्या कोई किराया चुकाया गया? फ़ाइल पर कुछ भी नहीं है. इस बात का भी कोई सुझाव नहीं है कि कथित किरायेदार को परिसर में कब शामिल किया गया था। फिर भी, याचिकाकर्ता द्वारा अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई है। इस प्रकार, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता केवल आदेश को चुनौती देने का बहाना ढूंढ रहा है। यह बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि कार्यवाही लंबित होने से पहले या उसके दौरान भी परिसर को किसी भी समय किराए पर दिया गया था।

(22) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, तीसरे प्रश्न का उत्तर भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिया जाता है।

(23) इस स्तर पर, श्री कपूर ने ब्याज और जुर्माने के साथ बकाया राशि का भुगतान करने की पेशकश की है। श्री अग्निहोत्री इस प्रार्थना का विरोध

करते हैं। उन्होंने बताया है कि याचिकाकर्ता यह पेशकश केवल इस तथ्य के कारण कर रहा है कि संपत्ति का मूल्य कई गुना बढ़ गया है।

(24) प्रतिवादियों ने एक स्पष्ट हलफनामा दायर किया है जो दर्शाता है कि दिसंबर 1998 में एक समान साइट रुपये 16,30,000 में बेची गई थी। तीन महीने से भी कम समय के बाद, उसी क्षेत्र में समान आयाम वाली एक और साइट रुपये 24,70,000 की राशि में बेची गई थी। याचिकाकर्ता इस संपत्ति को लगभग रुपये 6 लाख की मामूली रकम में हड़पना चाहता है। यदि यह अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, तो याचिकाकर्ता वर्ष 2001 में उस कीमत पर संपत्ति की वसूली करेगा जो वर्ष 1985 में देय थी। ब्याज और जुर्माना याचिकाकर्ता द्वारा किए गए डिफ़ॉल्ट के लिए प्रतिवादियों को उचित और न्यायसंगत मुआवजा नहीं होगा। प्रार्थना स्वीकार करने से जनता राजकोष को परिहार्य हानि होगी। व्यापक सार्वजनिक हित को व्यक्ति के हित से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार, हमें याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं मिलता है। फलस्वरूप इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

(25) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(26) उपरोक्त के मद्देनजर, हमें इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती। परिणामस्वरूप, इसे खारिज किया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा